बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 257 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 31 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, बैरिकेड्स की वेल्डिंग कर सुरक्षा और कड़ी

नई दिल्ली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के हालिया प्रदर्शन के बाद बुधवार को जंतर-मंतर पर एक बार फिर छात्रों और युवा संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने कई छात्र और युवा संगठनों के साथ मिलकर देश के अलग-अलग राज्यों में छात्र आंदोलनों पर हो रही पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार छात्रों, युवाओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई, उन पर दर्ज मामलों को वापस लेने और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

नीट पेपर लीक केस: 'आप ड्यूटी करें, जवाबदेही मेरी', विवाद के बीच सीआरपीएफ महानिदेशक ने जवानों को दिया बड़ा भरोसा

नई दिल्ली नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया। इस कथित बल प्रयोग को लेकर एक विवाद लगातार जारी है। इसी विवाद के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों और अधिकारियों को संबोधित किया। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में जवानों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए हर नेक इरादे वाले फैसले का समर्थन किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जहां जवाबदेही बनती है, वहां पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। यह बयान विशेष रूप से जवानों के मनोबल को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों पर बल प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। इस कथित बल प्रयोग के कारण एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बल के जवानों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान लिए गए अच्छे इरादों वाले हर निर्णय का समर्थन होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जवाबदेही तय होने पर पूरी जिम्मेदारी लेने की बात भी दोहराई। यह संदेश जवानों के आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

कांवड़ यात्रा आरंभ: दिल्ली में आज से 11 अगस्त तक विशेष यातायात व्यवस्था

नई दिल्ली । दिल्ली में सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने 30 जुलाई से 11 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया है। लाखों कांवड़ियों के राजधानी से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह व्यवस्था आम लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई है। यात्रा के दौरान 308 ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है और 306 ट्रैफिक रेगुलेशन प्वाइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में स्थापित 1,828 कांवड़ शिविरों के आसपास यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 9 से 11 अगस्त के बीच कांवड़ियों की संख्या सबसे अधिक रहने की संभावना है। इसे देखते हुए 9 अगस्त सुबह 7 बजे से कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू होंगे। सबसे अधिक असर जीटी रोड पर रहेगा। अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक का मार्ग 9 अगस्त सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा। कांवड़ियों के प्रवेश के लिए गाजीपुर, अप्सरा, भोपुरा, सोनिया विहार, लोनी, महाराजपुर और डीएलएफ बॉर्डर को प्रमुख मार्ग बनाया गया है। हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। यात्रा के दौरान जीटी रोड, वजीराबाद रोड, लोनी रोड, मथुरा रोड, रिंग रोड, पुस्ता रोड, आशाराम त्यागी मार्ग और जीटी करनाल रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। भारी वाहनों के लिए भी अलग डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की अपील की है। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही बृहस्पतिवार से राजधानी पूरी तरह शिवमय हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के प्रिय इस पावन महीने में दिल्ली के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने की उम्मीद है। श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर जलाभिषेक करेंगे। इस वर्ष 11 अगस्त को पड़ने वाली शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन होगा। सावन की शुरुआत के साथ ही गोमुख और हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़िये दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने लगेंगे। अगले कुछ दिनों में राजधानी के श्रद्धालु भी कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे और पूरा शहर ''बोल बम'' व ''हर-हर महादेव'' के जयघोष से गूंज उठेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर, मादीपुर के प्राचीन शिव मंदिर, यमुना तट स्थित नीली छतरी वाले मंदिर, प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर, छतरपुर, द्वारका, रोहिणी, शाहदरा, करोल बाग, जनकपुरी तथा अन्य प्रमुख शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मंदिर समितियों ने साफ-सफाई, पेयजल, बैरिकेडिंग, अलग-अलग दर्शन कतारें, प्रसाद वितरण और स्वयंसेवकों की तैनाती की व्यवस्था की है। कई मंदिरों में सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष रुद्राभिषेक, भजन-संध्या और धार्मिक प्रवचन भी होंगे। सावन भर मंदिरों के कपाट ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। मान्यता है कि इस माह श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी आस्था के कारण सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करेंगे। दिल्ली। सावन माह की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शहरों व गांवों को लौट रहे कांवड़िये दिल्ली से गुजर रहे हैं। हरियाणा व राजस्थान से आने वाले श्रद्धालु अपनी लंबी दूरी की यात्रा पहले ही शुरू कर देते हैं। भगवा वस्त्रों, कंधों पर कांवड़ व ''बोल बम'' के जयकारों से दिल्ली का माहौल शिवमय हो गया है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन, झिलमिल, वेलकम व आसपास के क्षेत्रों में टूटी सड़कें व गड्ढे कांवड़ियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों के पास बैटरी रिक्शा, ऑटो व अन्य वाहनों के खड़े रहने से रास्ते संकरे हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भीड़ से गुजरने में कठिनाई हो रही है। हरियाणा के अंकित अहलावत सहित कई कांवड़ियों ने बताया कि दिल्ली में खराब सड़कों व लंबे जाम के कारण कांवड़ के खंडित होने का डर बना रहता है।

दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात: 9वीं के छात्र के सीने में घोंपते रहे चाकू, दौड़ा-दौड़ाकर वार

नई दिल्ली उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर स्थित कर्दमपुरी इलाके में मंगलवार रात नौवीं कक्षा के एक छात्र इंतजार (17) की बेरहमी से चाकू और ईंट से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने कॉल कर बहाने से इंतजार को घर से बुलाया। घर से कुछ दूर पहुंचते ही आरोपियों ने उस पर ईंट और सीने में चाकू से हमला कर दिया।

पीड़ित जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहा और भीड़ तमाशबीन रही। किसी ने भी इंतजार को बचाने का प्रयास नहीं किया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में इंतजार को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल दिसंबर 2025 में एरिया में हुई एक युवक में परिवार को इंतजार पर भी शक था। पुलिस की जांच में इंतजार का कोई रोल हत्या में नहीं निकला था।

दूसरी ओर एरिया में रहने वाले एक दबंग अमन उर्फ बिट्टू से भी इंतजार की तू-तू-मैं-मैं हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसकी हत्या हुई। अपराध शाखा की टीम ने मंगलवार रात हुई हत्या के मामले में दो मुख्य आरोपी अरमान (18) और अलफैज (18) को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि इंतजार अपने परिवार के साथ गली नंबर-6, कर्दमपुरी में रहता था। इसके परिवार में पिता बाबू अली, मां और दो बहनें हैं। इंतजार इकलौता बेटा था। बाबू लाल का अपना कारोबार है। वहीं इंतजार एरिया के एक स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र था। मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। कुछ देर बाद रिहान नामक लड़के ने इंतजार को कॉल कर बुलाया। इसके बाद वह स्कूटी पर इंतजार को ले गया। रास्ते में दो और युवक स्कूटी पर बैठ गए। आरोप है कि गली नंबर-4, पुलिया पर पहुंचते ही आरोपियों ने इंतजार पर ईंट और चाकू से हमला कर दिया। रात 11 बजे पुलिस को खबर मिली।

सीजेपी का दूसरा बड़ा कदम: सीजेपी ने राकेश टिकैत से की मुलाकात

नई दिल्ली , कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में छात्र आंदोलन स्थगित होने के बाद सीजेपी ने अपने आंदोलन को बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ने के संकेत दिए हैं। सीजेपी के अनुसार, शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ अब किसानों और युवाओं के सवालों को भी साझा मंच पर उठाया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी नेताओं ने राकेश टिकैत से समर्थन मांगा। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय किसान यूनियन और सीजेपी आगे साथ में कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर छात्रों का उत्पीड़न नहीं रुका और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो पार्टी जल्द ही फिर से सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने

कहा, '20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की लाठियां और खून-खराबा झेला। अगर सरकार इतने पर भी नहीं चेती और युवाओं का उत्पीड़न जारी रहा, तो हम बहुत जल्द दोबारा सड़कों पर उतरेंगे।' यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया, जबकि पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि सरकार ने पहले सार्वजनिक रूप से भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और पुराने मामले भी वापस लिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कह रही है कि मामला अदालत में विचाराधीन है। दास ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि मंगलवार तक सरकार लिखित आश्वासन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाना बनाकर अपने वादे से पीछे हट रही है।

दिल्ली के शाहबाद डेयरी में देर रात गोलियां चलीं, हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर पकड़े

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक आरोपी कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह का कथित सदस्य है। पुलिस को आरोपियों के इलाके में होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी की। आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस दल पर गोलीबारी भी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घेर लिया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी की पहचान एक नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। आरोपियों ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। कुछ देर चली इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हिमांशु भाऊ गिरोह का कथित सदस्य बताया जा रहा है। यह गिरोह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। गिरोह रंगदारी, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस अब इन आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। नाबालिग आरोपी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर आठ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज

दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र, अपमानजनक और मानहानिकारक पोस्ट साझा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सात से आठ सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी कर संबंधित अकाउंट की पूरी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है।

स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ''एक्स'' को भेजे नोटिस में संबंधित पोस्ट को तीन घंटे के भीतर हटाने या उन तक पहुंच रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित अकाउंट से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डेटा, लॉग और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी बनाए गए अकाउंटों

के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) (आपराधिक धमकी), 353(2) (झूठी सूचना, अफवाह या चिंताजनक खबर फैलाना) और 356(2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई। जांच से जुड़े एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदेह के दायरे में आए कुछ पोस्ट हाल में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ''संसद चलो'' विरोध प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड किए गए थे। इन पोस्ट में प्रधानमंत्री और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तथ्यात्मक और कानूनी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, आईएफएसओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत ''एक्स'' से संबंधित अकाउंट धारकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईपी लॉग, लॉगिन-लॉगआउट विवरण और अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि पोस्ट करने वालों की पहचान की जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत भी ''एक्स'' को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कई चिह्नित यूआरएल तक तत्काल पहुंच रोकने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित सामग्री झूठी, छेड़छाड़ की गई और आपत्तिजनक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों की छवि धूमिल करना है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया मंच से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभी जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सम्पादकीय...

महिमामंडन

गाली इन दिनों राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई खुलेआम गंदी गालियां इसका बहाना बनी है। हैरत की बात है कि इसमें कई प्रोफेसर और पत्रकार भी शामिल हो गए हैं और इन गालियों को उचित ठहराने की दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। इसे लड़कियों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति बताया जा रहा है तो कई गालीबाजों को नई गालियां रचने का सुझाव दिया जा रहा है। उनके हिसाब से सारी गालियां पुरुषों द्वारा रची गई है, लिहाजा लड़कियों को नई तरह की गालियों की रचना करनी चाहिए। समाज का एक बड़ा तबका इसका विरोध भी कर रहा है। उसका कहना है कि गालियां भले ही समाज में सदा से चली आ रही हैं, लेकिन कम से कम उनकी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं रही है। गालियों के समर्थकों में सबसे बड़ी संख्या खुद को क्रांतिकारी मानने वाले वामपंथी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ भारत में वामपंथी विचारधारा के लिहाज से गठित हुआ था। उसके पहले अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। गाली विमर्श के संदर्भ में प्रेमचंद ने लिखा है, 'हर जाति के बोलचाल का ढंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आएगा। बोलचाल की गंभीरता और सुथरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदजुबानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का पक्का प्रमाण है। जितने गंदे शब्द हमारी जबान से निकलते हैं, शायद ही किसी सभ्य जाति की जबान से निकलते हों।' इसमें दो राय नहीं कि हर सफल आंदोलन के बाद आंदोलनकारी नायक और विजेता के रूप में उभरते हैं। इस लिहाज से काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता जंतर-मंतर आंदोलन के फिलहाल के विजेता तो हैं ही। इस तर्क से उनका साथ देने वाला समूह भी उसी वर्ग का माना जाएगा। इतिहास हमेशा विजेताओं का ही गुणगान करता है। चूंकि सीजेपी के नेता एक तबके के हीरो हैं, इसलिए उनकी ओर से दी गई गालियों को उनके गुणों के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय समाज में शादी-ब्याह और मुंडन-जनेऊ आदि के मौके पर प्यार से गालियां दी जाती हैं। लिहाजा जंतर-मंतर की गालियां भी उन्हीं गालियों की तरह स्नेह की अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? गालीबाजों का बचाव करने वाले क्या ऐसी ही गालियां अपने ही बच्चों के मुख से अपने ही घरों में सुनना पसंद करेंगे? गंभीरता से विचार करेंगे तो इसका जवाब 'नहीं' है। हर समाज में गालियां किसी न किसी रूप में रही हैं, लेकिन वे कभी सार्वजनिक स्वीकार्यता और विमर्श का विषय नहीं रही हैं। गालियां कभी यथार्थ नहीं होतीं। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति के लिए गालियों के प्रयोग की शुरुआत हुई, लेकिन आधुनिक यथार्थवादी चिंतन से पहले के साहित्य में कभी गालियों का प्रयोग नहीं होता दिखता। तर्क दिया जा रहा है कि जेन-जी की यही भाषा है। वे ऐसे ही खुद को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जेन-जी परीक्षा में भी गालियों को अपने जवाब में शामिल करते हैं? और क्या वह स्वीकार्य होगा? सवाल यह भी है कि जो पत्रकार इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या वे अपने अखबारों और अपने स्टूडियो में उन गालियों के इस्तेमाल को तैयार होंगे? निश्चित तौर पर इन सभी सवालों का जवाब 'नहीं' में है। फिर यह सवाल क्यों न उठे कि गालियों का महिमामंडन क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि जेन-जी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि समूचे देश का जेन-जी एक जैसा नहीं है। जरूरी नहीं कि दिल्ली और चंडीगढ़ के जेन-जी की तरह मुंबई और बेंगलुरु का जेन-जी भी सोचता हो। जेन-जी का एक हिस्सा भले ही गालियां देने में फख्र महसूस कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी उनका एक बड़ा हिस्सा संस्कारी है और उसे गालियां बकने से परहेज है। मार्क्सवादी हिंदी लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी ने एक जगह लिखा है कि गालियों को वैध ठहराने की कोशिश पुनरुत्थानवादी सोच की खूबी है। वह पुराने असभ्य रूपों, भाषाई प्रयोगों, आदतों और संस्कारों को बनाए रखता है। मार्क्सवादी राष्ट्रीय विचारधारा को पुनरुत्थानवादी ही मानते हैं, तो क्या मान लें कि गालियों को उचित ठहराने वाले मार्क्सवादी भी अब पुनरुत्थानवादी हो गए हैं? गालियां हमेशा से गलत और असभ्य मानी जाती रही हैं। महाभारत में शिशुपाल का प्रकरण आता है। उसकी सौ गालियों को श्रीकृष्ण बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शिशुपाल जब सौ की सीमा पार करता है तो उसका वध कर देते हैं। जाहिर है कि कृष्ण के दौर में भी गालियां असभ्यता की निशानी थीं। उनका महिमामंडन नहीं होता था। मध्यकाल में जरूर गालियों के मुख्यधारा का हिस्सा बनने के संकेत मिलते हैं। फिर भी उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता नहीं दिखती। ऐसे में प्रश्न यह है कि भारतीय समाज प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली गालियों और असभ्यता को क्यों स्वीकार करे? नई पीढ़ी को असभ्य-अभद्र बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा क्यों दिया जाए? सभ्यता के साथ मर्यादित शब्दों में कड़ी से कड़ी आलोचना करने और कठोर बातें बोलने के लिए उन्हें योग्य क्यों न बनाया जाए।

परीक्षा प्रणाली को जड़ से बदलने का अवसर

सृजन पाल सिंह

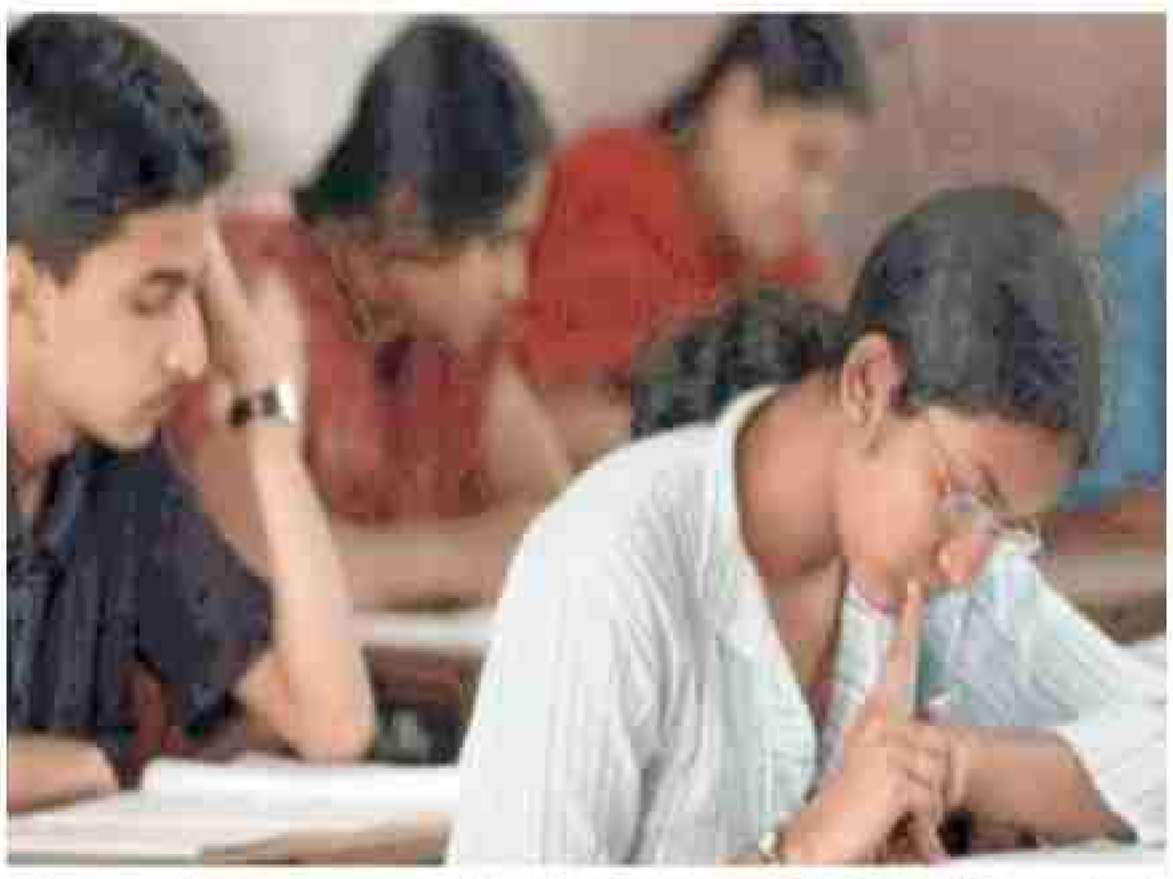

भारत की परीक्षा व्यवस्था इन दिनों अपने सबसे बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है। गत दिनों नीट-यूजी 2026 का प्रश्नपत्र लीक होने के कारण 23 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके विरोध में दिल्ली से लेकर देशभर में व्यापक छात्र आंदोलन हुए। जवाबदेही की मांग के बीच शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तथा एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसी बीच केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। राधाकृष्णन समिति ने वर्ष 2024 में भी यही सिफारिश की थी। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने युवाओं की आवाज सुनी है और सही दिशा में पहल की है, परंतु यह क्षण केवल एक परिवर्तन तक सीमित नहीं है।

जब पूरी परीक्षा प्रणाली कागज से स्क्रीन पर स्थानांतरित हो रही है तो आधा-अधूरा बदलाव क्यों किया जाए? जिस प्रकार वर्ष 1991 के आर्थिक संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नए द्वार खोले थे, उसी प्रकार वर्ष 2026 का परीक्षा-संकट भारतीय परीक्षा व्यवस्था को इक्कीसवीं सदी के अनुरूप बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है, बशर्ते हम दूरदर्शिता के साथ बड़ा सोचें। प्रस्तावित माडल जेईई मेन की तर्ज पर बहु-पाली सीबीटी का है, जिसमें प्रत्येक पाली के सभी परीक्षार्थियों को एक ही निर्धारित प्रश्नपत्र मिलेगा। यही ढांचा वर्ष 2021 में सेंध का शिकार हो चुका है। जेईई मेन 2021 पूरी तरह कंप्यूटर आधारित थी, फिर भी सोनीपत के एक परीक्षा केंद्र पर 'रिमोट एक्सेस' साफ्टवेयर के माध्यम से बाहर बैठे साल्वर परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्र हल कर रहे थे। सीबीआइ जांच के अनुसार, प्रति उम्मीदवार 12 से 15 लाख रुपये तक वसूले गए। साफ्टवेयर से छेड़छाड़ के आरोप में एक रूसी हैकर भी पकड़ा गया, जिससे कथित रूप से 800 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ पहुंचा। यदि निर्धारित प्रश्नपत्र और असुरक्षित मशीनें बनी रहीं तो चोरी का रास्ता बंद नहीं होगा, बल्कि वह केवल कागज से खिसककर स्क्रीन पर आ जाएगा। संसद की स्थायी समिति भी कह चुकी है कि वर्ष 2024 में एनटीए द्वारा आयोजित 14 परीक्षाओं में से पांच परीक्षाएं बाधित हुई थीं। इसीलिए हमें पूरी परीक्षा प्रणाली बदलनी होगी, क्योंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कोई रामबाण समाधान नहीं है।

अमेरिका की जीआरई जैसी परीक्षाएं केवल 'कंप्यूटर पर' आयोजित नहीं होतीं, बल्कि वे एडेप्टिव होती हैं। इनमें विशाल एन्क्रिप्टेड प्रश्नबैंक से प्रत्येक परीक्षार्थी को अलग, किंतु समान कठिनाई स्तर वाला प्रश्नपत्र मिलता है और परीक्षा पूरे वर्ष आयोजित की जाती है। इसी प्रकार, सैट वर्ष 2024 से पूरी तरह डिजिटल-एडेप्टिव हो चुकी है। इसमें दो परीक्षार्थियों के प्रश्न एक जैसे नहीं होते, इसलिए 'पेपर लीक' की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसे परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक सत्यापन और 'लाक्ड-डाउन' टर्मिनल होते हैं, जिन पर कोई बाहरी साफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। ब्रिटेन की यूकैट भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह रटे हुए ज्ञान के बजाय अभ्यर्थी की निर्णय-क्षमता का मूल्यांकन करती है। अपने देश की बात करें तो कैट परीक्षा भी वर्षों से कंप्यूटर आधारित, बहु-पाली प्रणाली के तहत सफलतापूर्वक आयोजित होती आ रही है और उसमें किसी बड़े स्तर की सेंधमारी देखने को नहीं मिली है। अर्थात समाधान का रास्ता हमारे सामने है और वह कोई अबूझ भी नहीं। हमारी परीक्षाएं प्रतिभा नहीं, बल्कि स्मरण-शक्ति का आकलन करती हैं। जो परीक्षा देश के भावी डाक्टरों का चयन करती है, वह केवल यह देखती है कि अभ्यर्थी ने जीव-विज्ञान कितना रटा है। जबकि इसकी परख बोर्ड में पहले ही हो चुकी होती है। नीट परीक्षा यह नहीं परखती कि अभ्यर्थी में मरीज का दर्द समझने की संवेदना, तेजी से सीखने की क्षमता और दबाव की स्थिति में सही निर्णय लेने का विवेक है या नहीं। इसी रटंत प्रणाली ने 58 हजार करोड़ रुपये के कोचिंग उद्योग को जन्म दिया है, जिसके लिए अनेक माता-पिता कर्ज तक लेने को विवश हो जाते हैं। 'एक दिन का जुआ' आज भी यथावत बना हुआ है। केवल स्क्रीन पर परीक्षा आयोजित कर देने से इनमें से कोई भी समस्या स्वतः समाप्त नहीं हो जाएगी। सबसे पहले सीबीटी को एडेप्टिव बनाया जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय एन्क्रिप्टेड प्रश्नबैंक तैयार किया जाए और प्रत्येक विद्यार्थी को अलग, किंतु समतुल्य कठिनाई स्तर वाला प्रश्नपत्र मिले, जो परीक्षा शुरू होते ही परीक्षा केंद्र के टर्मिनल पर तैयार हो। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र का स्वतंत्र सुरक्षा आडिट, बायोमीट्रिक सत्यापन तथा रिमोट एक्सेस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। गांवों और कस्बों तक परीक्षा केंद्रों का व्यापक नेटवर्क स्थापित हो तथा निःशुल्क माक परीक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि डिजिटल खाई किसी ग्रामीण प्रतिभा को निगल न सके। प्रत्येक बड़ी परीक्षा वर्ष में दो या तीन बार आयोजित हो और अभ्यर्थी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर ही मान्य माना जाए। इससे प्रश्नपत्र लीक का काला बाजार खत्म हो जाएगा। डाक्टरों के चयन के लिए संवेदना और निर्णय-क्षमता का आकलन करने वाले परिदृश्य-आधारित प्रश्न तथा साक्षात्कार जोड़े जाएं। सिविल सेवा परीक्षा में भी तथ्य-स्मरण पर निर्भरता घटे और केस-स्टडी आधारित प्रश्न बढ़ाए जाएं। कुछ प्रश्न ओपन-बुक भी हों। जो परीक्षा रटने की नहीं, बल्कि सोचने और समझने की होगी, उसका प्रश्नपत्र लीक होने पर भी नकल करने वालों को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा और रटवाने पर आधारित कोचिंग उद्योग भी सिमटने लगेगा। वर्ष 2024 का सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 10 वर्ष तक के कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान करता है। आवश्यकता उसके कठोर और निष्पक्ष क्रियान्वयन की है। प्रत्येक परीक्षा से पहले साफ्टवेयर का स्वतंत्र तकनीकी आडिट कराया जाए तथा मूल्यांकन में डबल-ब्लाइंड आन-स्क्रीन जांच की व्यवस्था हो, जिसमें एआइ जोड़ संबंधी त्रुटियों और छूटे हुए उत्तरों की पहचान करने में सहायता करे। आज का भारत बेहतर शिक्षा, विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था और रटंत-आधारित परीक्षा तंत्र से मुक्ति की मांग कर रहा है।

गुरु पूर्णिमाः भगवा ध्वज, हिंदुत्व और राष्ट्र निर्माण की अखंड चेतना

नंदन जैन

भारतीय जीवन-दर्शन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो मनुष्य के भीतर चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और राष्ट्रभक्ति का प्रकाश प्रज्वलित करती है। गुरु ही व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए जीने का मार्ग दिखाता है। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से प्रवाहित एक जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है।

इसकी आत्मा वेदों, उपनिषदों, ऋषियों, संतों, महापुरुषों और गुरु-शिष्य परंपरा में बसती है। गुरु पूर्णिमा इसी अमर परंपरा का महापर्व है, जो हमें ज्ञान, संस्कार, सेवा और राष्ट्रधर्म के प्रति पुनः समर्पित होने की प्रेरणा देता है। भारतीय जीवन-दर्शन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो मनुष्य के भीतर चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और राष्ट्रभक्ति का प्रकाश प्रज्वलित करती है। गुरु ही व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए जीने का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस महान गुरु परंपरा को एक अनूठी और कालजयी अभिव्यक्ति दी है। संघ में किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं माना जाता, बल्कि भगवा ध्वज को गुरु के रूप में वंदन किया जाता है। इसका संदेश अत्यंत स्पष्ट और प्रेरक है-व्यक्ति सीमित होता है, किंतु आदर्श अमर होते हैं। भगवा ध्वज त्याग, तप, बलिदान, सेवा, शौर्य, आत्मसंयम और सनातन भारतीय संस्कृति की अखंड चेतना का प्रतीक है। यह प्रत्येक स्वयंसेवक को निरंतर स्मरण कराता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्तिगत जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य समाज एवं मातृभूमि की सेवा है। लगभग एक शताब्दी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सेवा, संगठन और राष्ट्रनिष्ठा की ऐसी परंपरा विकसित की है, जिसने भारत के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य, शिक्षा, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा और जनजागरण जैसे अनेक क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की निस्वार्थ भागीदारी इस विचार को साकार करती है कि राष्ट्र निर्माण केवल विचारों से नहीं, बल्कि सतत सेवा और समर्पण से होता है। हिंदुत्व का वास्तविक स्वरूप भी इसी सांस्कृतिक चेतना में निहित है। हिंदुत्व किसी संकीर्ण आग्रह का नाम नहीं, बल्कि भारत की सनातन सभ्यता, सांस्कृतिक निरंतरता और जीवन मूल्यों का व्यापक दर्शन है। यह सत्य, करुणा, सहअस्तित्व, समरसता, कर्तव्य, आध्यात्मिकता और लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त करता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' तथा 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' जैसे सनातन सूत्र इसी उदात्त दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं। राष्ट्रवाद भी केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति आत्मीय श्रद्धा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानने का जीवन मूल्य है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को राष्ट्रसेवा का माध्यम बना लेता है, तभी एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव होता है।

आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास यात्रा को समान गति से आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, उसकी सफलता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास, सामाजिक एकता, सेवा भाव और राष्ट्रीय चरित्र की मजबूती से सुनिश्चित होगी। गुरु पूर्णिमा हमें इसी राष्ट्रीय चेतना को अपने जीवन का आधार बनाने का संदेश देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहें, भगवा ध्वज के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करें, सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को आत्मसात करें और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा का भाव पहुँचाएँ। यही सच्चे अर्थों में गुरु परंपरा का सम्मान है और यही भारत को पुनः विश्व के नैतिक एवं सांस्कृतिक नेतृत्व के शिखर पर स्थापित करने का मार्ग भी है। आइए, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि सेवा हमारा संस्कार बने, समरसता हमारी पहचान बने और 'राष्ट्र प्रथम' हमारा जीवन मंत्र बने। यही गुरु के प्रति सच्चा आदर, सम्मान होगा।

स्तरहीन चर्चा

अंततः पेपर लीक विरोधी संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से भी इस विधेयक के पारित होने के आसार हैं। इस विधेयक पर संसद की मुहर लगने के साथ ही पेपर लीक विरोधी कानून और अधिक कठोर हो जाएगा, लेकिन यह समय बताएगा कि वह परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले तत्वों को हतोत्साहित करने में सफल होगा या नहीं? निःसंदेह परीक्षाओं में सेंध लगने की समस्या को देखते हुए पेपर लीक विरोधी कानून को कठोर किया ही जाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि कड़े कानून एक सीमा तक ही प्रभावी होते हैं। आवश्यकता इसके उपाय करने की भी है कि पेपर लीक हो ही न सके। आशा की जाती है कि नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में गठित समिति की ओर से सुझाए गए उपायों पर अमल करने में भी तत्परता दिखाई जाएगी। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि देश में पेपर लीक कराने वाला एक माफिया पैदा हो गया है। यह माफिया इसलिए पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ी है, जो छल-छद्म से परीक्षा पास करना चाहते हैं। इसी के साथ स्कूली परीक्षाओं में भी नकल की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जो छात्र स्कूली परीक्षाओं में नकल करके पास होते हैं, वही आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं को अनुचित तरीके से पास करने के जतन करते हैं। स्पष्ट है कि पेपर लीक की समस्या के पीछे कहीं न कहीं समाज का चारित्रिक पतन भी जिम्मेदार है। इसे इससे समझा जा सकता है कि छात्रों और अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षक भी पेपर लीक में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह एक विडंबना रही कि लोकसभा में पेपर लीक विरोधी कानून को और कठोर किए जाने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तो खूब हुए, लेकिन पेपर लीक की समस्या के लिए उत्तरदायी नैतिक पतन की ओर ध्यानाकर्षण नहीं किया गया। कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे कई जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं, जिन पर छल-कपट के सहारे पास होने के आरोप लगे हैं? यह निराशाजनक रहा कि लोकसभा में पेपर लीक विधेयक के गुण-दोष पर बहुत कम चर्चा हुई। पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करता रहा और शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था की कमियों पर गंभीर चर्चा करने के लिए आगे नहीं आया। जो चर्चा हुई भी, वह स्तरहीन ही रही। ऐसा लगा कि पक्ष-विपक्ष की रुचि पेपर लीक के लिए एक-दूसरे को दोषी बताने की रही। कुछ नेता तो ऐसे रहे, जिन्होंने पेपर लीक विधेयक पर कुछ कहा ही नहीं। इसके बजाय वे इधर-उधर की बातें करते रहे। इनमें नेता विपक्ष राहुल गांधी भी रहे। उनका भाषण एक तरह से इसका परिचायक रहा कि किसी गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा कैसे न की जाए।

बांग्लादेश से व्यापार के लिए पुतिन ने भारतीय रुपए पर लगाया दाँव

नीरज कुमार दुबे

रूस ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार भारतीय रुपये में निपटाया जाए। इसके साथ ही मॉस्को एक विशेष भुगतान तंत्र विकसित करने, ढाका में रूसी बैंक की शाखा खोलने तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग संपर्क स्थापित करने की भी पहल कर रहा है। रूस ने बांग्लादेश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने का प्रस्ताव देकर दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में नई हलचल पैदा की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने राजदूत सर्जियो गोर को तुरंत ढाका जाने का निर्देश दे डाला। इन दोनों घटनाक्रमों को साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। एक ओर रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत की वित्तीय ताकत का सहारा लेकर बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना चाहता है, वहीं दूसरी ओर चीन और रूस के साथ ढाका की बढ़ती नजदीकियों ने वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने अपने शीर्ष राजनयिक को ढाका भेजने का फैसला किया है। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रुपया, क्षेत्रीय कूटनीति और हिंद-प्रशांत की बदलती रणनीतिक राजनीति एक साथ जुड़ी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि रूस ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार भारतीय रुपये में निपटाया जाए। इसके साथ ही मॉस्को एक विशेष भुगतान तंत्र विकसित करने, ढाका में रूसी बैंक की शाखा खोलने तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग संपर्क स्थापित करने की भी पहल कर रहा है। यह प्रस्ताव रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पन्न वित्तीय संकट का सीधा जवाब है। प्रतिबंधों के कारण रूसी बैंक वैश्विक भुगतान प्रणाली से काफी हद तक कट गए हैं और इसी वजह से मॉस्को चीन, तुर्किये और भारत जैसे देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस ने चीनी युआन की बजाय भारतीय रुपये को प्राथमिकता दी है। इससे पहले रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के ऋण भुगतान के लिए युआन का विकल्प सामने आया था, लेकिन चीन और बांग्लादेश के बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम के कारण भुगतान प्रक्रिया का हिस्सा बनने से हिचक गए। परिणामस्वरूप अरबों डॉलर की ऋण किस्तें अभी भी सोनाली बैंक में रूस के नाम खोले गए खाते में फंसी हुई हैं। ऐसे में भारतीय रुपया रूस के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। यह भारत की वित्तीय विश्वसनीयता और रुपये के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी संकेत है। बताया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश-रूस अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि रूस केवल भुगतान व्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रूस-बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल, वस्त्र निर्यातकों का पंजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सहयोग तथा कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव लेकर आया है। मॉस्को ने बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय बाजार से 10 डॉलर प्रति टन कम कीमत पर लगभग 2.8 लाख टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में भी रुचि दिखाई है। दूसरी ओर ढाका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार, कृषि, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को अपनी प्राथमिकता बना रहा है। देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह घटनाक्रम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि रूस और बांग्लादेश के बीच व्यापार भारतीय रुपये में होता है, तो यह दक्षिण एशिया में रुपये के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को नई गति देगा। इससे डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम होगी और भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय सेतु के रूप में उभर सकता है। यह भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति के भी अनुकूल है जिसके तहत वह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र के निर्माण पर जोर दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सर्जियो गोर का 30 जुलाई का ढाका दौरा विशेष महत्व प्राप्त करता है। सर्जियो गोर, जो दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत होने के साथ भारत में अमेरिका के राजदूत भी हैं, वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही में चीन की यात्रा कर चुके हैं और बीजिंग के साथ व्यापार, आर्थिक गलियारे तथा रक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनी है। विशेष रूप से बांग्लादेश-म्यांमार आर्थिक गलियारे के चीनी प्रस्ताव ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। यही वह बिंदु है जहां पूरी तस्वीर स्पष्ट होती है। रूस आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ना चाहता है, चीन अवसंरचना और सामरिक संपर्क के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका इस बढ़ती रूस-चीन धुरी को संतुलित करने के लिए सक्रिय हो गया है। सर्जियो गोर का ढाका दौरा इसी रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन यह समझता है कि यदि बांग्लादेश रूस और चीन के साथ गहरे आर्थिक एवं सामरिक रिश्ते विकसित करता है, तो बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद-प्रशांत तक शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए वॉशिंगटन अब ढाका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को प्रत्यक्ष रूप से समझना और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है। दूसरी ओर, भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम अवसर इसलिए है कि रूस भारतीय रुपये को क्षेत्रीय भुगतान की धुरी बनाना चाहता है और बांग्लादेश पहले से ही भारत के साथ कुछ व्यापार रुपये में करता है। साथ ही भारत के लिए यह घटनाक्रम चुनौती भी है क्योंकि यदि चीन का आर्थिक गलियारा और रूस की वित्तीय व्यवस्था समानांतर रूप से मजबूत होती है, तो दक्षिण एशिया की भू-राजनीति पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। भारत को ऐसे समय संतुलित कूटनीति, मजबूत आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय नेतृत्व के माध्यम से अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करना होगा। बहरहाल, स्पष्ट है कि यह केवल व्यापारिक प्रस्ताव या एक राजनयिक यात्रा की कहानी नहीं है। यह उस नए एशियाई शक्ति-संतुलन का संकेत है जिसमें डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राएं, प्रतिबंधों की जगह वैकल्पिक वित्तीय तंत्र और पारंपरिक गठबंधनों की जगह बहुध्रुवीय समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। बांग्लादेश इस नई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता दिख रहा है और भारत उसकी धुरी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पोल्लापेला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08893)

रेल परियोजनाओं के विस्तार पर मुख्यमंत्री साय की पहल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई विस्तृत चर्चा

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार एवं लंबित रेल परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पांडे भी उपस्थित रहे। बैठक में कटघोरा-डोंगरगढ़ रेलवे लाइन परियोजना को रेलवे मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से विकसित किए जाने पर सहमति बनी।

लगभग 295 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी, जिससे अब तक रेलवे नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों को रेल संपर्क मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना की प्रगति की भी जानकारी दी। बताया गया कि इस 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा रेलवे द्वारा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किमी), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किमी) तथा अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किमी) नई रेल लाइनों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए इन परियोजनाओं की स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र किए जाने की बात कही। बैठक में किरंदुल-कोतागुडेम (180 किमी) तथा गढ़चिरोली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) (490 किमी) नई रेलवे लाइन परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य को भी शीघ्र पूरा करने पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक एवं आदिवासी अंचलों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।

श्यामकरण टेकरीवाल ने संतों का आशीर्वाद लेकर दिया समरसता का संदेश

बहराइच। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरा जनपद श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के रंग में रंगा नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत जिले के लगभग दो सौ मंदिरों में एक साथ पूजा-अर्चना, संत सम्मान, कलश यात्रा, 65 दीपों का दीपोत्सव और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों ने विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर संतों, महंतों और पुजारियों का सम्मान किया तथा समाज में समरसता, समानता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का संदेश दिया। निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्यामकरण टेकरीवाल ने मंदिर में विधिवत पूजन-अर्चन कर संतों एवं पुजारियों का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, जबकि संत गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समानता, मानवता और सद्भाव का अमर संदेश देता है। आज समाज को उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय ने मरी माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर संतों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि संतों की शिक्षाएं समाज को जोड़ने और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देती हैं। गुरु रविदास का समरस समाज का सपना आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके समय में था।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत गुरु रविदास की जन्मस्थली से उनके 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ किया है। जन्मस्थली की पावन माटी से भरे 131 कलश देशभर के विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं, ताकि संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को 20 हजार से अधिक स्थानों तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान के तहत बहराइच के करीब 200 मंदिरों में 65 दीपों का दीपोत्सव आयोजित किया गया। दीपों की रोशनी, शंखनाद, भजन-कीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबे रहे। श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित के संकल्प को दोहराया। जिला मीडिया प्रभारी शिवांकर शुक्ला ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि संत परंपरा के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाना है। जिला, मंडल एवं बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।

महिला थाना को मिली नई कमान, उप निरीक्षक प्रियांशु भट्ट ने संभाला कार्यभार

अम्बेडकरनगर। जनपद के महिला थाना को नई प्रभारी मिल गई हैं। गुरुवार को महिला उप निरीक्षक प्रियांशु भट्ट ने महिला थाने पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला थाना आने वाली प्रत्येक पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा और उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा विश्वास को मजबूत करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान भी निरंतर चलाए जाएंगे, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

माटीकला बोर्ड स्थापना पखवाड़े के तहत जागरूकता कार्यक्रम, कारीगरों को योजनाओं की दी जानकारी

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के स्थापना के नौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ÷माटीकला बोर्ड स्थापना पखवाड़ा÷ के अंतर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य माटीकला से जुड़े कारीगरों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों को बोर्ड की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामगोपाल उर्फ गोपाल अंजान ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक माटीकला को नई पहचान दिलाने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कारीगरों से बोर्ड की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने माटीकला टूल किट वितरण योजना, माटीकला रोजगार योजना, माटीकला शिल्पकारी योजना तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और मिलने वाले लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए 200 से अधिक कारीगरों एवं उद्यमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी कराया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड ओमप्रकाश गोला प्रजापति, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर जिलाधिकारी (नगर), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), भारतीय स्टेट बैंक एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के अधिकारी, फाइन आर्ट विशेषज्ञ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महिला अधिवक्ताओं ने जाना एक दूसरे का परिचय

बाथरूम व गन्दगी को लेकर जाहिर किया रोष

फतेहपुर। जिला बार एसोसिएशन के कलेक्ट्रेट स्थित हाल में गुरूवार को महिला अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी ने एक दूसरे का परिचय जाना। साथ ही अधिवक्ताओं ने बाथरूम व गन्दगी को लेकर रोष जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव में तो इस समस्या को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है, जिससे सभी अधिवक्ताओं को असुविधा होती है। बैठक में रश्मि रस्तोगी एडवोकेट, निशा गुप्ता एडवोकेट, प्रीती पटेल एडवोकेट, पप्पी राजपूत एडवोकेट, नीलम द्विवेदी, महनाज खातून एडवोकेट, साक्षी सिंह यादव एडवोकेट, प्रियंका एडवोकेट, मदीहा रिजवान एडवोकेट, शिवानी मौर्य एडवोकेट, अलफिशा एडवोकेट, अपर्णा मिश्रा एडवोकेट, निकिता एडवोकेट, अंजलि एडवोकेट, रुकिया अयूब एडवोकेट, पूनम द्विवेदी एडवोकेट, कोमल एडवोकेट, प्रीती एडवोकेट, ऐश्वर्या श्रीवास्तव एडवोकेट, नमिता एडवोकेट, गीता देवी एडवोकेट, निशा मौर्या एडवोकेट, पूनम सिंह एडवोकेट, सीमा देवी एडवोकेट, फातिमा बेगम एडवोकेट, रानी द्विवेद एडवोकेट, सीता द्विवेदी एडवोकेट व निशा यादव एडवोकेट के अलावा अन्य महिला अधिवक्ता मौजूद रहीं।

टीएमयू में फार्मेसी एक्सपर्ट बोले, एआई बनेगी स्वास्थ्य संग समग्र शिक्षा का आधार

मुरादाबाद। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा के फैकल्टी ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज के डीन रिसर्च एंड डवलपमेंट एवम् सेंटर ऑफ आईपीआर स्टडीज के निदेशक प्रो. हरीश दुरेजा ने कहा, आधुनिक चिकित्सा और अनुसंधान में एआई का उपयोग ड्रग डिस्कवरी, प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स और मरीजों की व्यक्तिगत देखभाल में तेजी से बढ़ रहा है। एनईपी- 2020 के तहत डिजिटल परिवर्तन को अपनाकर फार्मेसी स्टूडेंट्स वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और नवाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को समग्र शिक्षा के महत्व को समझाते हुए केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर तकनीकी कौशल विकसित करने की सलाह दी। साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया- पीसीआई की ओर से जारी फार्मेसी के नए पाठ्यक्रम और उसमें एआई के अनुप्रयोगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार से एनईपी- 2020 के लक्ष्य साकार हो सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई, भविष्य में एआई स्वास्थ्य देखभाल और समग्र शिक्षा का आधार बनेगी।

नेपाल में बढ़ता तनावः सुनसरी हिंसा की आंच सिराहा तक, गोलबाज़ार में कर्फ्यू, दो मौतों के बाद हालात गंभीर

कपिलवस्तु, नेपाल। नेपाल के सुनसरी जिले में हुई सांप्रदायिक झड़प की आग अब तराई के अन्य जिलों तक फैलती दिखाई दे रही है। सुनसरी के दीवानगंज ग्रामीण नगरपालिका- 3 स्थित कप्तानगंज में रविवार रात दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। घायल एक और युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है, जबकि कई लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इस घटना के विरोध में सिराहा सहित कई जिलों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम लागू कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, दीवानगंज ग्रामीण नगरपालिका- 3 के 22 वर्षीय जय प्रकाश मेहता की विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज के दौरान दोपहर 1:24 बजे मृत्यु हो गई। मोरंग पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले इसी घटना में ओम प्रकाश मेहता की भी मौत हो चुकी थी। दोनों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना में घायल अन्य आठ लोगों का विराटनगर के विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। वहीं सुरक्षाकर्मियों सहित 22 से अधिक लोग इस हिंसा में घायल बताए जा रहे हैं। सुनसरी की घटना के विरोध में गुरुवार सुबह से सिराहा जिले में प्रदर्शन तेज हो गए। कई स्थानों पर तनावपूर्ण स्थिति बनने और आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने गोलबाज़ार क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर

दिया। जिला सुरक्षा समिति की आपात बैठक के बाद जारी आदेश के अनुसार, गुरुवार दोपहर 2 बजे से अगले आदेश तक गोलबाज़ार के संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही, सभा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन और सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्फ्यू लागू होते ही नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई। मुख्य राजमार्गों और संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तनाव के बीच सिराहा के गोलबाज़ार स्थित क्रमॉल में आग लगा दी गई। इसके अलावा कई स्थानों पर तोड़फोड़ और हिंसक घटनाओं की भी सूचना है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील कर रहा है।

गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री करेंगे दौरा

नेपाल के गृह मंत्री सुधन गुरुंग गुरुवार को सुनसरी पहुंचकर हिंसा में जान गंवाने वाले ओम प्रकाश मेहता और जय प्रकाश मेहता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता भी दीवानगंज ग्रामीण नगरपालिका- 3 स्थित घटना स्थल का दौरा करेंगी। दोनों मंत्री प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ तराई की सुरक्षा स्थिति पर हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद सुनसरी रवाना हो रहे हैं।

जांच जारी, शांति बनाए रखने की अपील

नेपाल पुलिस ने बताया है कि रविवार रात कप्तानगंज में दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद स्थिति हिंसक हो गई थी। घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन ने नागरिकों से संयम बरतने, अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिन महिलाओं के हैं तीन बच्चे, नहीं मिलेंगे 2500 रुपये! आप-कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली । प्रदेश सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर राजधानी की सियासत गरमा गई है। भाजपा इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और चुनावी वादा पूरा करने वाला कदम बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पात्रता की शर्तों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि कड़ी शर्तों के कारण ज्यादातर महिलाएं योजना से बाहर हो जाएंगी, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए योजना का बचाव किया। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को 2,500 की सहायता से वंचित कर रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में योजना की शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हर महिला को 2,500 देने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि अधिकांश महिलाएं लाभ से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना से बाहर रखने, 10 वर्ष का निवास प्रमाण मांगने, छोटे मामलों में भी अपात्र घोषित करने तथा बिजली खपत जैसी शर्तों पर आपत्ति जताई। सौरभ ने दावा किया कि सरकार 17 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात कर रही है, जबकि वास्तविकता में केवल करीब पांच लाख महिलाएं ही पात्र होंगी। उन्होंने योजना को 62 लाख महिलाओं के साथ धोखा और 'भद्दा मजाक' बताया। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने राजनीतिक कारणों से केंद्र की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। सहरावत ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद लंबित केंद्रीय योजनाएं लागू की गईं और अब दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा भी पूरा किया जा रहा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वुमेन-लेड डेवलपमेंट' विजन को आगे बढ़ाती है। उनके अनुसार, 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की करीब 17 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सौरभ भारद्वाज लगातार तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआती 16 महीनों में ही महिला सम्मान राशि योजना का पहला चरण शुरू कर दिया है, जिससे 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने सौरभ भारद्वाज के इस आरोप को भी गलत बताया कि जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को ज्ञापन भेजकर दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना में लगाई गई शर्तों को वापस लेने और चुनावी वादे के अनुरूप सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने की मांग की है।

सदन में राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें? अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन और अवमानना का दिया नोटिस

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया। इस कदम से संसद में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए गए? अनुराग ठाकुर ने यह नोटिस किस आधार पर दिया? अब लोकसभा में इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है?

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया है। अनुराग ठाकुर ने तीन पन्नों के नोटिस में लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करे। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन और गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। भाजपा सांसद का कहना है कि इस तरह की भाषा संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

राहुल गांधी पर कौन से नियम के उल्लंघन का आरोप?

नोटिस में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 29 जुलाई को एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित बातचीत का जिक्र किया। उनका आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा के नियम 352 का उल्लंघन किया। नोटिस में कहा गया कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जो प्रमाणित नहीं थे और जिनसे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।

विशेषाधिकार समिति से क्या मांग की गई?

अनुराग ठाकुर ने अपने नोटिस में कहा कि मामले की पूरी जांच विशेषाधिकार समिति से कराई जाए। उनका कहना है कि समिति यह तय करे कि राहुल गांधी की टिप्पणी से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ या नहीं। उन्होंने समिति से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय मर्यादा बनी रहे।

अब इस मामले में आगे क्या होगा?

लोकसभा अध्यक्ष के पास नोटिस पहुंचने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसदीय नियमों के अनुसार होगी। अध्यक्ष यह तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है तो समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

राहुल के इडियट वाले बयान पर क्या बोले थे अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन के बाहर बुधवार को राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था अगर राहुल गांधी ने किसी छात्र के लिए इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने यह शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि हम इसका स्वागत करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा है कि राहुल गांधी को अब इसका एहसास हो गया, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह टिप्पणी एंटी-पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान के बाद की।

जहां का सांसद अवैध लाइसेंस बनवाने में व्यस्त, वहां के भगवान ही मालिक

सीएम योगी का अफजाल पर निशाना

वाराणसी । गाजीपुर में सीएम योगी ने सपा सांसद अफजाल अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां के सांसद अवैध शस्त्र लाइसेंस बनवाने में व्यस्त, वहां के भगवान ही मालिक हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी में सब चंगा है, नो टेंशन। दंगाई अब जेल में हैं। माफिया किसी के नहीं होते, ये समाज का खून चूसते हैं। ये कब्र में जाकर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार ने पहले ही दिन तय किया था दंगाइयों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। दंगा करने वाले आज मिट्टी में दफन हो गए हैं अब माफिया किसी भी बेटी की तरफ नजर उठाने से पहले डरते हैं। उन्हें पता है कि कहीं मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने गहमर गांव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने इसे एशिया और देश का सबसे बड़ा गांव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गहमर को 12,000 फौजियों के गांव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि अकेले इसी गांव में 12 हजार से अधिक फौजी और सैन्य अधिकारी निवास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत में जब भी देश की सीमाओं की रक्षा की बात आती है, तो गाजीपुर के फौजियों का योगदान अविस्मरणीय है। जिले के सैनिकों ने 1961, 1965 और 1971 के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, कारगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। यह गाजीपुर की वीर भूमि का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई और भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हमीद इसी गाजीपुर की धरती से थे। उन्होंने बताया कि गाजीपुर राष्ट्र रक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर यह गौरवशाली जिला क्यों गुमनाम हो गया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गाजीपुर की पहचान का संकट खड़ा किया था, उन्हें समाज ने सजा दी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं होने दिया। इसके विपरीत, सपा और कांग्रेस सालार और गाजी के नाम पर मेले आयोजित करते रहे हैं। योगी ने कहा कि उनकी सरकार गाजीपुर के वास्तविक नायकों को सम्मान दे रही है।

वांगचुक ने की रेलवे की तारीफ, परीक्षा सुधार से लेकर एंटी पेपर लीक बिल पर बोले?

नई दिल्ली)। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने भारतीय रेलवे की सराहना की है। वहीं, परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से बीजेपी के साथ हुए समझौते के पालन का भी आग्रह किया। ट्रेन में सफर करते हुए अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात माध्यम है। दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की जो सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चेनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। मुझे भारतीय रेल पर बहुत गर्व है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर कहा, मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में विधेयक लाया गया। उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो। ये जारी रहे। दूसरी अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने पहले मेरे साथ लिखित में और फिर बीजेपी के साथ जो समझौते हुए थे कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। एफआईआर नहीं करेंगे। वह उस पर कायम रहें। उसका पालन करें। देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं, सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं।

पंजाब पेपर लीक पर बवाल, दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत

नई दिल्ली पंजाब में कथित प्रश्नपत्र रिसाव के मामले को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इस गंभीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कार्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। भाजपा कार्यकर्ता पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रश्नपत्र रिसाव से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। भाजपा इस मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। यह प्रदर्शन पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

सावन का पहला दिन: सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक

वाराणसी । सावन माह के पहले दिन बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के षोडशोपचार दर्शन-पूजन किए और जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। इसके साथ ही उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा कालभैरव के दर्शन-पूजन किए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद बाबा कालभैरव मंदिर में भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सस्वर भैरवाष्टकम् स्तोत्र के बीच मंगल कामना के लिए आरती भी उतारी। मुख्यमंत्री के इस प्रवास का उद्देश्य सावन माह में प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना करना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काशी प्रवास के दौरान प्रदेशवासियों के कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना की।

उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर मंदिर के शिखर को प्रणाम किया और गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना में भाग लिया। सावन माह के आरंभ होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन के पहले दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भोर से ही दर्शनार्थियों का तांता लगना शुरू हो गया था। गंगा घाट से लेकर मंदिर तक, श्रद्धालुओं की कतारें देखने को मिलीं। भक्तों ने विधि-विधान से जलाभिषेक किया और देवाधिदेव महादेव से सुख-समृद्धि की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के साथ, देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं।

'बिना चुनाव जीते 6 महीने से अधिक समय तक कोई मंत्री कैसे रह सकता है', दीपक प्रकाश पर सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार से सवाल

नई दिल्ली बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश निर्वाचित न होने के बावजूद छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया है।

जिसमें वकील ने कहा है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली 6 महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई मंत्री छह महीने की सीमा समाप्त होने से ठीक पहले पद से हटकर, नई सरकार बनते ही दोबारा शपथ लेकर समय सीमा को 'रीसेट' (शून्य) कर सकता है। इसको लेकर CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को बिहार सरकार से यह सवाल पूछा कि यह पूरी तरह से कानून का मामला है। राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री छह महीने से अधिक समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है? गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 अप्रैल, 2026 को पद छोड़ने से पहले दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री के रूप में चार महीने और 26 दिनों तक कार्य किया, जिसके साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद अगले 22 दिनों तक उन्होंने कोई भी मंत्री पद नहीं संभाला।

7 मई, 2026 को सम्राट चौधरी द्वारा नई सरकार बनाने के बाद, प्रकाश ने निर्वाचित न होने के बावजूद फिर से मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 30 मई को दायर याचिका में उनकी नियुक्ति को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। क्योंकि, दीपक प्रकाश अब तक कुल मिलाकर छह महीने से अधिक समय से पद पर बने हुए हैं, जबकि वे किसी भी सदन के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं। अनुच्छेद 164(4) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने पर मंत्रियों को निर्वाचित होने के लिए छह महीने की छूट अवधि प्रदान करता है। इसमें कहा गया है, 'कोई भी मंत्री जो लगातार छह महीनों की अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।' बिहार का मामला इसलिए अलग है क्योंकि मंत्री दीपक प्रकाश ने लगातार छह महीने तक पद पर कार्य नहीं किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वे चार महीने और 26 दिन तक मंत्री रहे, जो छह महीने की छूट अवधि के भीतर था। इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी द्वारा फिर से नियुक्त किए जाने के बाद से दीपक प्रकाश ने कुछ महीने ही सेवा की है। लेकिन कुल मिलाकर, वे बिना निर्वाचित हुए छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहे हैं। बता दें कि किसी मंत्री के पदभार ग्रहण करने के महीनों बाद उसे निर्वाचित कराने की प्रथा अपने आप में विवादास्पद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी मंत्री के लिए छह महीने की समय सीमा से पहले इस्तीफा देना, कुछ दिनों बाद फिर से पदभार ग्रहण करना और यह दावा करना कि छह महीने की अवधि नए शपथ ग्रहण की तारीख से फिर से शुरू हो जाएगी, यह कानूनी रूप से कितना सही है?

'पैलेट गन से घायल हुए लोगों का इलाज कराए दिल्ली सरकार', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए लोगों का अच्छी तरह से इलाज कराएं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज कराया जाए, और खासकर उन लोगों का जो कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश आईबी के पूर्व विशेष निदेशक और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे यशोवर्धन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग की गई है और साथ ही छात्र आंदोलन के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती और उनके गोला बारूद के इस्तेमाल के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। कोर्ट ने माना कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी के नियमों के तहत पुलिस विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस बागची ने कहा, 'पुलिस के नियम खास हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, जब तक कि आप खुद उन नियमों को ही चुनौती न दें।

चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के कदमों में से एक कदम पैलेट गन का इस्तेमाल है।'

भारतीय टीम की भगवा जर्सी को लेकर क्यों मचा बवाल?

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आगामी पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप से पहले हॉकी इंडिया ने टीम की पारंपरिक नीली जर्सी की जगह नारंगी (ऑरेंज) रंग की जर्सी लॉन्च की है। इस फैसले पर पूर्व भारतीय कप्तान वीरेन रसक्विन्हा ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर भारतीय हॉकी की पहचान रहे नीले रंग को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस विवाद पर हॉकी इंडिया का जवाब भी आया है। भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम दशकों से नीली जर्सी में खेलती आई है। यही रंग भारतीय हॉकी की पहचान बन चुका है। नई ऑरेंज जर्सी सामने आने के बाद पूर्व कप्तान वीरेन रसक्विन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हॉकी इंडिया ने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह फैसला निराशाजनक है।

अनुष्का के शरीर पर टैटू, दस मिनट विवाद, छात्रा को मारीं तीन गोलियां, हिस्ट्रीशीटर ने भी दी जान

मेरठ । मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ने 12वीं की छात्रा को तीन गोलियां मारी और फिर खुदकुशी कर ली। युवती के टैटू गुदवाने पर आरोपी ने डिफेंस एन्क्लेव में वारदात को अंजाम दिया। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा कि वारदात से पहले दोनों के बीच दस मिनट तक विवाद हुआ था। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके के डिफेंस एन्क्लेव में मंगलवार शाम जोनल पार्क के पास शिवलोकपुरी निवासी हिस्ट्रीशीटर आदित्य प्रधान (22) ने न्यू गोविंदपुरी निवासी 12वीं की छात्रा अनुष्का (19) को तीन गोलियां मारीं। इसके बाद आरोपी ने खुद भी सीने में दो गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। सिर में एक और पेट में दो गोलियां लगने से अनुष्का लहूलुहान होकर गिर पड़ी। उसका सुभारती अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालत चिंताजनक बताई गई है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले के अनुसार, अनुष्का ने शरीर पर कोई टैटू गुदवाया था। इसी लेकर आदित्य शक करने लगा था। इसी विवाद को लेकर वारदात की गई है। पुलिस अफसरों और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की। पुलिस ने दो अवैध पिस्टल और पांच कारतूस के खोखे बरामद किए। आदित्य और अनुष्का एक दूसरे से चार साल से परिचित थे और उनमें वारदात से पहले दस मिनट तक विवाद हुआ था। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी डिफेंस एन्क्लेव में मंगलवार शाम चार बजे ताबड़तोड़ पांच गोलियों की आवाज सुनकर निवासी सहम गए। पार्क में टहल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो आदित्य प्रधान और अनुष्का जोनल पार्क के पास सड़क पर लहूलुहान हालत में जमीन पड़े थे। निवासियों ने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आदित्य की मौत हो चुकी थी। अनुष्का को कैलाशी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे सुभारती रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि शिवलोक पुरी निवासी आदित्य ने वर्ष 2025 में आईटीआई की पढ़ाई की थी। उस पर छह से अधिक जानलेवा हमले समेत हथियार तस्करी की प्राथमिकी दर्ज है। वह कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर था। गत 16 जून को वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। वह अनुष्का को लगभग चार साल से जानता था। जेल से आने के बाद से वह छात्रा से बात करने का प्रयास कर रहा था। छात्रा ने उससे बात करने से मना कर दिया था। आदित्य ने छात्रा को बुधवार शाम डिफेंस एन्क्लेव के जोनल पार्क के पास बुलाया था। छात्रा स्कूटी से और आदित्य बाइक से वहां पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दोनों के बीच किसी बात पर करीब दस मिनट तक नोकझोंक और कहासुनी हो रही है। इसी बीच आदित्य ने पिस्टल निकालकर अनुष्का को तीन गोलियां मार दीं। इसके बाद आरोपी ने खुद के सीने में दो गोलियां मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके से अनुष्का और आदित्य के मोबाइल, उनकी स्कूटी व बाइक भी कब्जे में लिए हैं। पुलिस इनकी पड़ताल कर रही है। इसके अलावा पुलिस परिजनों से पूछताछ कर वारदात का सही कारण पता लगाने का प्रयास कर रही है। आदित्य और अनुष्का का घर डिफेंस एन्क्लेव से लगभग तीन किमी दूर है। दोनों की कॉलोनियां आसपास हैं। दोनों अनुसूचित जाति के हैं। पुलिस ने एहतियातन दोनों के घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि इस मामले में देर रात तक छात्रा के परिजनों ने तहरीर नहीं दी है।

'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' यूपी पुलिस पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्तता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश के थाने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के केंद्र नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों का स्थान बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने बलिया के रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चलाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे संरक्षण दिए जाने के मामले को गंभीर भ्रष्टाचार का मामला माना. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को पूरे मामले की जांच कर रसड़ा थाने में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

सक्षम भारत

सक्षम भारत की बेवसाइड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।